

जयपुर को वैश्विक मान्यता मिलने पर उपमुख्यमंत्री ने जताई प्रसन्नता

जनसुनवाई में आमजन को तुरंत राहत

जयपुर।राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमार ने आज सिविल लाईंस स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं। अतिक्रमण, पुलिस से संबंधित मामले और स्थानीय विकास से जुड़ी अनेक समस्याएं प्रमुख रही। उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से संवाद कर कई मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया।

उन्होंने कहा, "हम हर सोमवार और मंगलवार को जनसुनवाई कर रहे हैं ताकि आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। डबल इंजन की सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है, जिससे हर नागरिक को राहत मिले।"

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने जयपुर को 2025 में विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिलने पर हर्ष और संतोष व्यक्त किया, और इसे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उपलब्धि बताया।



उपमुख्यमंत्री दिया कुमार ने सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की।

उन्होंने कहा, यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, डबल इंजन सरकार की नीतियों और राजस्थान सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है। इसमें आमजन की सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण

रही है।

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन अवसंरचना, सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास

■ **उपमुख्यमंत्री ने जयपुर को 2025 में विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिलने पर हर्ष और संतोष व्यक्त किया, और इसे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उपलब्धि बताया**

के लिए चल रही योजनाओं से राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है।

उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह मान्यता उन सभी लोगों की मेहनत का प्रतिफल है, जो राजस्थान की अतिथि परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और सौंदर्य को दुनिया के समक्ष प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

शिविर में 240 मरीजों की नेत्र जांच

जयपुर। शेखावाटी अग्रवाल समाज संस्था के तत्वावधान में व संजय एंड ज्योति अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से 150 वॉनिशुल्क लैंस प्रत्यारोपण शिविर विद्याधर नगर, सेक्टर-7 स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में आयोजित किया गया।240 मरीजों ने आंखों की जांच की गई,साथ ही 182 व्यक्तिओं को चर्चमे वितरण किए गए। इस मौके पर सुरेश अग्रवाल, अरुण कांबरा, राजेंद्र मोदी , अनिल शर्मा , मुकेश बंसल, दिनेश टेकरीवाल, मुकेश मीणा व राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

शासन सचिव पर्यटन ने दो दिवसीय तीज उत्सव के आयोजन की रूप रेखा पर चर्चा की

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति व पुरातत्व राजेश यादव की अध्यक्षता तथा पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड़ एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में तीज का उत्सव और अधिक भव्यता से मनाने और तीज माता की शोभायात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारी के सम्बन्ध में सोमवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव ने कहा कि इस बार 27 एवं 28 जुलाई को जयपुर में इस बार दो दिवसीय तीज उत्सव का आयोजन पहले से और अधिक भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा।जिसमें राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति और परम्पराएं अद्भुत व आकर्षक रूप से प्रदर्शित होंगी। तीज उत्सव में जयपुर के आम नागरिक और देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन ने दो दिवसीय तीज उत्सव के सम्पूर्ण आयोजन की रूप रेखा पर चर्चा करते हुए बताया कि तीज माता के शोभायात्रा में इस बार राजस्थान की लोक कलाओं में उत्कृष्ट रूप से परांपरा लगभग 200 लोक-

■ **प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव की अधिकारियों की उपस्थिति में तीज माता की शोभायात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारी के सम्बन्ध में बैठक ली**

कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने कहा मेले में महिलाओं के द्वारा तैयार सामान का क्राफ्ट मार्केट लगाया जाएगा। मेले में फूड स्टाल्स् के साथ महिलाओं के लिए झुले, मेहन्दी माण्डण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि पॉण्डीक पार्क में लोक कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाएगा। इसी प्रकार छोटी चोपड़ पर तीज माता की पूजा की जाएगी एवं कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान जयपुर के इस अत्यंत लोकप्रिय तीज उत्सव के आयोजन का विभिन्न विभागों की वेबसाईट ,पर्यटन विभाग की वेबसाईट और सोशल मीडिया

प्लेटेफॉर्म्स पर वृहद प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की कवरेज प्रिन्ट मीडिया,इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया इम्पल्सएसर्स के द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार तीज उत्सव का लाइव प्रसारण जयपुर शहर में स्थित स्क्रीन्स एवं सर्पूण राजस्थान में डीओआईटी के माध्यम से प्रसारण करवाया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने शोभायात्रा में लवाजमा हेतु हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल, बैण्ड, शहनाई-नगाड़ा, आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने देशी-विदेशी पर्यटकों के बैठने हेतु हिन्दु होटल के टेरेस एवं निचें बरामदों में बैठने की व्यवस्था करने, वहां टेण्ट एवं वाटर प्रूफ शामियाना भी लगवाने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव की ओर से बैठक में जयपुर नगर निगम (हैरिटेज) आयुक्त को तीज माता की सवारी मार्ग में आने वाले पेड़ों को छटाई, बिजली के तार एवं अन्य केबल तार जो की सवारी मार्ग में झूल रहे है उन्हें दुरस्त करवाने के निर्देश दिए गए।

सीवेज लाइन डालने से पूर्व करें सुरक्षा और समयबद्धता की प्लानिंग : आवासन मंत्री

जयपुर । अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और सीवेज के काम की प्लानिंग आमजन की ज़रूरतों, सुरक्षा और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को ध्यान में रखकर की जाए। यह कहना है नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रां का।

सोमवार को डीएलबी मुख्यालय के सभागार में आयोजित हुई रूडसिको की 60 वीं बोर्ड बैठक की खरां अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में पिछली बोर्ड बैठक के कायो द्वारा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजना की समीक्षा की गई तथा योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिए गये।

मंत्री झाब्बर सिंह खर्रां ने कहा की सीवेज का काम शुरू करने से पहले ही उसकी निर्माण अवधि , गुणवत्ता और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए ताकि किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि ना हो। सीवेज के इनलेट और आउटलेट के निर्माण का विशेष ध्यान रखा जाए । सीवरेज ड्रेनेज परियोजना की डी.पी.आर. निर्माण के समय विशेष ध्यान रखें तथा क्रियान्वयन में किसी



झाब्बर सिंह खर्रां ने (बीच में) डीएलबी मुख्यालय पर रूडसिको की बोर्ड बैठक ली।

प्रकार की कमी न रहे। डी.पी.आर. की शुद्धता एवं उसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित तकनीकी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को भी नोटिस जारी कर उनपर जुर्माना लगाया जाए ताकि विषय में ऐसी कोई समस्या ना आए । उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया, खर्रां ने कहा की

■ **इस बैठक में पिछली बोर्ड बैठक के कायो द्वारा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजना की समीक्षा की गई तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिये**

रूडसिको का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है।

इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ देबाशीष पट्टि ,स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, पीएचईडी विभाग के मिशन निदेशक रवीन्द्र गोस्वामी, आवासन आयुक्त डॉं रश्मि शर्मा, रूडसिको के कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीणा, डीएलबी निदेशक प्रतीक जुईकर, वित्तीय सलाहकार उम्मेद सिंह, मुख्य अभियंता अरुण व्यास, प्रदीप गंगा सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

‘वक्फ बोर्डों की संपत्ति का डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल’

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद वक्फ बोर्डों की संपत्ति का डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए 6 जून को उम्मीद केंद्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल शुरू करने के साथ ही देशभर में राज्यों द्वारा वक्फ संपत्तियों का डेटा अपडेट करना भी शुरू कर दिया। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के बेहतर, पारदर्शी, सक्षम और सुविधाजनक प्रबंधन में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह जानकारी राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने सदन में दी।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन,दक्षता, सशक्तिकरण और विकास अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद

■ **राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित राज्यों ने संपत्तियों का डेटा अपडेट करना किया शुरू : राज्यसभा सांसद मदन राठौड़**

केंद्रीय पोर्टल-2025 को शुरू किया। पोर्टल शुरू करने के साथ ही महज डेढ़ माह में राज्यों ने इस पर डेटा अपडेट करना शुरू कर दिया। इस पोर्टल पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली,राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने डेटा अपडेट करना शुरू दिया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के उपयोग से वक्फ संपत्ति का गुपचुप तरीके से दुरुपयोग रहेगा॥ पहले जानकारी के अभाव में

मुड़ी भर लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं होता था कि कौन-कौन सी संपत्ति वक्फ की है। अब सभी को सब पता रहेगा। मंत्रालय पोर्टल शुरू करने के साथ-साथ इसका फॉलोअप भी करेगा। सेंट्रल वक्फ कार्डसिल, राज्यों के वक्फ बोर्ड और मंत्रालय की तकनीकी टीम ने इस पोर्टल को समावेशी बनाने में कड़ी मेहनत की है।

मदन राठौड़ ने बताया कि उम्मीद पोर्टल और डाटाबेस, रिफॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या को स्वचालित रूप से उत्पन्न करेगा। इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों और संपत्तियों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए किया जाएगा। अधिसूचितनियमों के अनुसार, मुलवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल का उपयोग करके पोर्टल और डाटाबेस पर इन्हें नामांकित करेंगे।

नव-निर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत

जयपुर। बिरला ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्यावर जिले के नव – निर्वाचित राजस्थान नर्सज एसोसियेशन संगठन के जिलाध्यक्ष जेठाराम ना प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्यारेलाल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ,रमेश सौनी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ,प्रदेश महिला मंत्री मालती शर्मा ,प्रदेश महामंत्री जेपी कसवा एवं प्रदेश प्रवक्ता सुनील शर्मा आदि ने जिलाध्यक्ष जेठाराम , पदाधिकारी ओमप्रकाश, प्रेम सहित अन्य सदस्यों का जोरदार स्वागत अभिनन्दन किया।

जेठाराम ने संकल्प लिया कि नर्सज संगठन हेतु जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे पूर्ण- निष्ठा से निभाएंगे और शीघ्र ही ब्यावर जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

सामूहिक शिवलिंग पूजन में हो रहा आस्था से खिलवाड़

■ **नदी में करने थे पार्थिव शिवलिंग विसर्जित, कचरे के कट्टे में डाल दिए**

जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गईं। इस आयोजन में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी उपस्थित रहे। लेकिन कार्यक्रम के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने आस्था को शर्मसार कर दिया। सोमवार दोपहर तक पूजन सामग्री जहां-तहां बिखरी रही। पार्थिव शिवलिंग प्लास्टिक के कट्टे में कचरे के साथ पड़े मिले। कई पार्थिव शिवलिंग खुले में इधर-उधर फैले हुए थे। न तो विधिवत विस्र्जन हुआ, न ही किसी प्रकार की धार्मिक मर्यादा का पालन किया गया। रोली, मोली, चावल, पुष्प सहित पूजन सामग्री पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी।

इसके अलावा मिट्टी के पार्थिव

शिवलिंग को गलने से बचाने के लिए उन पर चांदी की वर्क चढ़ाई गई। जानकारी के अनुसार चांदी के गंगय की खाल में कूट-कूट कर बनाई जाती है, जो धार्मिक दृष्टि से न केवल आपत्तिजनक है बल्कि शिव भक्ति की मूल भावना के खिलाफ है। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के दौरान ज्यादातर आयोजक चांदी की वर्क के बजाय प्लास्टिक की पतली पत्ती का उपयोग करते हैं।

दक्षिणा के साथ प्रायोजक भी करते हैं सहयोग:- ऐसे आयोजनों में स्वयंसेवी संगठनों और कथित धार्मिक समूहों द्वारा भारी दक्षिणा लेकर धर्म को व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। श्रद्धालु भक्ति में रमे रहते हैं, लेकिन पदों के पीछे कुछ लोगों द्वारा आस्था को बाजार बना दिया गया है। यजमानों से दक्षिणा के साथ-साथ ये लोग भामाशाहों से भी सहयोग के नाम पर मोटी राशि ले लेते हैं।

न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन जारी

जयपुर । प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य सरकार की ओर से कैंडर पुनर्गठन नहीं करने के विरोध में सोमवार को सामूहिक अवकाश जारी रहा। इसके चलते अदालतों में अधिकतर मामलों में तारीखें दी गईं। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के चलते नए मुकदमे भी टायर नहीं हो पा रहे हैं।

जब तक कैंडर पुनर्गठन का आदेश उनके हाथ में नहीं आएगा, तब तक उनका सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 25 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का हवाला देते हुए सामूहिक अवकाश समाप्त करने को कहा गया था, लेकिन अब आवासन से काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप लुहाड़िया ने राज्य सरकार व हाईकोर्ट प्रशासन से न्यायिक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी व पूर्व जिलाध्यक्ष बुजेश शर्मा की भूख हड़ताल आठवें दिन भी जारी रही।

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कट ऑफ से अर्थिक अंक लाने के बावजूद भी अभ्यर्थी को लाइब्रेरियन भर्ती- 2024 की चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जस्टिस सुरेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सायर चौधरी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 14 फरवरी, 2024 को लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता ने ओबीसी वर्ग में भाग लेकर 212 अंकों प्राप्त किए, जबकि इस वर्ग की कट ऑफ 179 आई थी। याचिकाकर्ता के एक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक के बजाए 39.34 अंक आने पर उसे चयन से वंचित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 7 फरवरी, 2024 को परिपत्र जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन किया था। संशोधन के तहत लाइब्रेरियन ग्रेड

■ **अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जस्टिस सुरेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सायर चौधरी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए**

द्वितीय और तृतीय के लिए हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम चालीस फीसदी अंक लाने के प्रावधान को हटा दिया गया था। याचिका में कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद याचिकाकर्ता को चयन से बाहर कर दिया गया, जबकि उसके कट ऑफ से काफी अधिक अंक हैं। ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।

‘स्वच्छ सर्वेक्षण में जियो फेंसिंग और मोबाइल ऐप से होगा डेटा संग्रह’

जयपुर। स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में इस बार जियोफेंसिंग और मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह किया जाएगा।

इतना ही नहीं, स्वच्छता मापदंडों पर नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की ओर से इस बार नागरिक प्रतिक्रिया एप्लिकेशन विकसित की गई है। डेटा संग्रहण साफ्टवेयर में जियो फेंसिंग को शामिल करने के साथ परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। यह जानकारी राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल मंत्री जी.सोमण्णा ने सदन में दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में इस बार देशभर के 34 राज्य एवं संघ राज्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही देशभर के 761 जिले और 21000 गांवों को शामिल किया गया है। गांवों के स्वच्छता अवलोकन के दौरान सेवा स्तरीय प्रगति, गांवों में स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन, संयंत्रों की कार्यशीलता का प्रत्यक्ष अवलोकन और नागरिक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में कुल 1 हजार अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा।

‘जयपुर में बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास हो सुनिश्चित’

■ **जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश**

जलभराव, सड़क क्षित, बिजली गड़बड़ी या अन्य समस्या की सूचना जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, जयपुर कंट्रोल रूम नंबर 0141-2204475,0141-2204476 के साथ-साथ टोल फ्री नंबर 1077 पर दी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में 9, नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा 4, नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा 3 नियंत्रण कक्षों का निरंतर संचालन किया जा रहा है। वहीं, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, मौसम विभाग, जयपुर मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, एस्सीआरएफ, नगर निगम, संचालन किया जा रहा है। वहीं, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, मौसम विभाग, जयपुर मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, एस्सीआरएफ, नगर निगम, संचालन किया जा रहा है।

हर आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद है टीम जयपुर जिला प्रशासन प्रशासन ने निचले इलाकों, जलभराव प्रभावित क्षेत्रों तथा पुराने बाढ़-प्रभावित इलाकों की पहचान कर विशेष निगरानी टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम को निर्धारित क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था, जनसंपर्क एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जांचे, एस्सीआरएफ, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों तैनात की गई हैं, जो आपदा की स्थिति में तुरंत राहत पहुंचा सकें। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं एवं साथ ही अतिरिक्त जिला कलक्टर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।